विलम्ब-शुल्क

*412. श्री बृहस्पति प्रसाद : क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च-अप्रैल 1964 में कलकत्ता बन्दरगाह में ब्रिटेन से आयात की गई इस्पात की पत्तियों को उतारने के लिये लोडिंग एजेंटों की नियुक्ति में देरी होने से लोहा और इस्पात नियंत्रण को 14,113 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो देरी होने के क्या कारण थे तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्रश्न में जो बातें पूछी गई हैं उन सब का प्रकरण आडिट रिपोर्ट (सिविल) 1967 में आता है । यह रिपोर्ट 7 अप्रैल 1967 को सभा पटल पर रखी गई थी । लोक लेखा समिति इन सभी बातों की भली प्रकार जांच करेगी । अतः समिति द्वारा इन बातों की जांच पूरी कर लेने से पूर्व सरकार के लिए इन मामलों पर कुछ कहना उचित न होगा ।

Company Law Tribunal

***413. Shri P. K. Deo:**
Shri K. P. Singh Deo:
Shri Dhirendranath:

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Company Law Board has recommended that the Company Law Tribunal be wound up; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). The Company Law Board has made no such recommendation but Government propose to abolish the Companies Tribunal and to make consequential amendments to the Companies Act. The reasons for the proposal to abolish the Tribunal are as follows:

(i) Experience of the functioning of the Tribunal for the first three years has not been very encouraging in realising the objectives with which it was set up namely quick findings as it had to adopt meticulous and time-consuming judicial procedure and proceedings before it were also liable to be stayed by appeals from its interim orders or by writ petitions before the High Courts.

(ii) The physical work-load of the Tribunal has been very light and persons affected in places outside Delhi have found it difficult and expensive to avail themselves of its powers.

G.M. Eastern Railway

***414. Dr. Mahadeva Prasad:**
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Y. S. Kushwah:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the General Manager of the Eastern Railway was *gheraoed* by railway employees on the 21st May, 1967; and

(b) if so, the demands of the employees and Government's reaction thereto?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). A demonstration by a number of workers led by the office bearers of a dissident and hitherto unrecognised group of the Eastern Railwaymen's Union was staged in the Office of the General Manager, Eastern Railway, on the

20th May and not on the 21st May. The demonstrators surrounded the car of the G. M. at the time of his leaving the office and after detaining him for some time, they dispersed after presenting a Memorandum to the General Manager containing several demands relating to the recognition of the dissident group of the Eastern Railwaymen's Union, trade union rights etc. Most of these demands had been examined in the past and not found acceptable. They will continue to be examined on their merits.

Export of Iron Ore to Japan

***415. Shri Chintamani Panigrahi:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Japanese firms have expressed the desire to pay 15 shillings extra per ton of iron ore, if it is exported from Paradeep Port in Orissa;

(b) if so, the action being taken by Government to increase the iron ore export from Paradeep; and

(c) whether it is a fact that the M.M.T.C. has offered a reduced price to the Japanese firms to accept iron ore from the port like Calcutta?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

कानपुर के औद्योगिक संस्थानों से वसूल किये जाने वाला रेलवे भाड़ा

*416. श्री शिवचरण लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के औद्योगिक संस्थानों अर्थात् जुगी लाल कमला पत, लक्ष्मी रतन काटेन मिल्स, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, म्युर मिल्स आदि औद्योगिक संस्थानों से 1 अप्रैल 1966 तक की अवधि के लिये रेलवे भाड़े तथा इन संस्थानों में रेलवे द्वारा बनाई रेलवे साइडिंग्स की रखरखाव के लिये खर्च के लिये कुल कितनी राशि वसूल करनी शेष है ; और

(ख) इस अत्यधिक बकाया राशि को वसूल करने के लिये रेलवे प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) उल्लिखित फर्मों और कुछ अन्य फर्मों के जिम्मे बकाया भाड़ा और अनुरक्षण प्रभार के सम्बन्ध में एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT.—584/67]

(ख) रेल प्रशासन फर्मों से सम्पर्क स्थापित करता है और पत्र लिख कर निवेदन करता है कि बकाया रकम का भुगतान करें । यदि इससे कोई परिणाम नहीं निकलता तो रेल प्रशासन उन्हें चेतावनी देता है कि यदि एक निश्चित अवधि में बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया तो रेलवे उनके माल को रोक लेगी जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत रेलवे को ग्रहणाधिकार प्राप्त है या साइडिंग में माल डिब्बे पहुंचाना बन्द कर देगी । यदि इस नोटिस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता तो दी गयी चेतावनी पर अमल किया जाता है ।

700 H.P. Diesel Locomotives

***417. Shri Hem Raj:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 700 H.P. diesel locomotives have been designed by the Railway Research, Designs and Standards Organisation for the Narrow Gauge Section;

(b) if so, whether their manufacture has been undertaken and at which place; and

(c) by what time these locomotives will be put on the rails on the narrow-gage sections and which narrow-